

wants that the hon. Minister should look into the matter, then he is governed by the contract or agreement entered into, under the general powers, if any. If that is so, then, the hon. Minister will look into it; if he can spare a copy for me, I shall also look into it and find out whether it is his jurisdiction or the jurisdiction of the Labour Minister, or whether Government have no control over this, and they can do as they like.

Shri Narayanankutty Menon: That is right. The only point is that the retrenchment orders given to these employees show that they have become surplus because of the economy measures. We are only surprised and sorry that this hon. Minister, after his experience, such a long experience, with the oil companies, should have tried to tell us what is given out by the companies....

Mr. Speaker: Order, order. I would not allow this question. Now, next question.

पंजाब में निर्वाचन व्यवस्था

१७४५. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२ के मापान्य निर्वाचनों के लिए तथाकथित पंजाबी क्षेत्र में मतदान पत्र और निर्वाचक नामावलियां केवल पंजाबी भाषा (गुरुमुखी लिपि) में ही छपायी जायेंगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन सम्बन्धी अन्य साहित्य भी उस क्षेत्र में केवल पंजाबी में ही छपाया जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय किया है और कुछ और निर्णय करने वाला है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस कारण पंजाबी क्षेत्र के बहुत से मतदाताओं को बहुत कठिनाई अनुभव होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या निर्णय करना चाहती है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरतबीस) :

(क) निर्वाचन आयोग ने हिदायत की है कि (चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र के सिवाय) पंजाबी क्षेत्र के सभी निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां पंजाबी में छपी जायें और चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां हिन्दी और पंजाबी दोनों भाषाओं में साथ साथ छपी जायें ।

(ख) से (ङ) निर्वाचन आयोग ने आम हिदायत दी है कि मतपत्र पर दी जाने वाली केफियत निर्वाचन क्षेत्र में या उसके बड़े भाग में प्रचलित प्रादेशिक भाषा में छपी जायें । निर्वाचन क्षेत्र का नाम अंग्रेजी में छपा जायेगा । जहां तक संसदीय और विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उम्मीदवार के लिये नियत प्रतीक भी मतपत्र पर छपा जायेगा । इसलिए अगर पंजाबी क्षेत्र में मतपत्रों के विवरण केवल पंजाबी में छपा जाते हैं तो उससे किसी भी पढ़े-लिखे वर्ग के मतदाता को किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा ।

चाहे क्षेत्र में प्रचलित भाषा कोई भी हो फार्म और अन्य निर्वाचन सम्बन्धी पुस्तिकाएं जनता को पंजाबी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध होंगी, चूँकि ये सभी पुस्तिकाएं और फार्म थोड़े मूल्य पर उपलब्ध होंगी, अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी उस क्षेत्र में इन में से उस भाषा वाली प्रति खरीद सकेगा जिस भाषा वाली प्रति को वह खरीदना चाहता है ।

Some hon. Members: In English also.

Shri Hajarnavis: (a) The Election Commission has directed that the electoral rolls for all constituencies comprised in the Punjabi Region except Chandigarh Capital area) should be printed in Punjabi and that the electoral rolls for the Chandigarh Capital area should be printed in diglot, that is, both Hindi and Punjabi.

(b) to (c). The Election Commission has issued a general direction that the particulars on a ballot paper should be printed in the regional language prevailing in the constituency or in a major portion thereof. The name of the constituency is to be printed in English. So far as Parliamentary and Assembly constituencies are concerned, the symbol allotted to a candidate is also to be printed on the ballot paper. No difficulty will therefore, be experienced by any section of the literate voters and I submit that it will also apply to illiterate voters—if the particulars on the ballot paper are printed only in Punjabi in the Punjabi Region.

The forms and other election pamphlets will be available to the public both in Punjabi and in Hindi, irrespective of the prevailing language of the Region. As all these pamphlets and forms will be available at a small price, it will be open to a person to purchase them in the language in which he desires to have them in either Region.

Mr. Speaker: If it were a long reply, the hon. Minister could have laid it on the Table of the House.

श्री प्रकाश बीर शास्त्री : श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि जैसे कि माननीय मंत्री ने बतलाया कि चंडीगढ़ के अतिरिक्त तथाकथित पंजाब क्षेत्र में चुनाव सम्बन्धी मतपत्र और दूसरे चुनाव सम्बन्धी प्रकाशन सब पंजाबी भाषा के अन्दर होंगे तो क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि उस भाषा की लिपि गुरुमुखी होगी और यदि हाँ तो क्या आपने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि उस क्षेत्र में अधिकांश व्यक्तियों की संख्या ऐसी भी है जो कि गुरुमुखी लिपि से सर्वथा अपरिचित हैं और इस कारण क्या उनको अपना मतपत्र आदि देने में असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा ?

श्री आर० एम० हजरतबीस : अब अगर कोई भाषा नहीं जानते और पढ़ नहीं

सकते तब तो उनके लिए कोई सवाल ही नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि जब निर्वाचन आयोग ने यह आम हिदायत दी है कि मतपत्र पर दी जाने वाली कैफियत निर्वाचन क्षेत्र में या उसके बड़े भाग में प्रचलित प्रादेशिक भाषा में छापी जाये तो उन्होंने जरूर सब बातों पर गौर कर लिया होगा ।

श्री प्रकाश बीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह था कि तथाकथित पंजाबी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि गुरुमुखी लिपि से अपरिचित हैं और इसलिए निर्वाचन आयोग को अपना निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जितने भी व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो कि हिन्दी पढ़ सकते हैं उनको हिन्दी में मतपत्र दिये जाये और जो गुरुमुखी पढ़े हुए हैं उनको गुरुमुखी में मतपत्र दिये जाय, दोनों प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए थीं । निर्वाचन आयोग ने क्या इस प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व इस सम्बन्ध में कोई जानकारी ले ली थी कि उनको इन असुविधाओं का सामना करना नहीं पड़ेगा ?

श्री आर० एम० हजरतबीस : मैं समझता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने ऐसी आम हिदायत देने से पूर्व सब चीजों पर सोच विचार कर लिया होगा ।

Mr. Speaker: What was the reply of the hon. Minister? We could not hear it.

Shri Hajarnavis: I was saying that before the Election Commission issued that direction, they must have considered all these matters.

Shri Tyagi: In the matter of election procedure, they are not the final authority. I thought that they ought to have consulted the Law Ministry, particularly when they are designing the ballot paper in only one language. The ballot paper is not to be dropped in the box on the basis of symbols now. A cross-mark has to be made and then it has to be put in the box.

Therefore, every voter must know the name against which he is making that cross-mark.

Shri Hajarnavis: Where the population speaks more than one language, choice of language has got to be made. It may be that in an area more than two languages may be spoken. It is not possible to provide ballot paper in every language spoken by every voter in the place.

Some Hon. Members rose—

Shri Tyagi: How are they doing it in Chandigarh?

श्री रघुनाथ सिंह: चंडीगढ़ में दो नैर्गुरजिज होंगी, वहाँ पर क्या होगा ?

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Hajarnavis: May I make the answer clear? First of all, so far as the literature is concerned, it is printed in both languages.

Shri Tyagi: That is immaterial. Literature is not so material as the ballot paper.

Shri A. C. Guha: And the voters' list.

Mr. Speaker: What is the difficulty? It is not so much the enforcement of any particular language or *lipi* as to enable every citizen who is entitled to vote being given facilities to vote, unless the facilities demanded are to vote being given facilities to vote, in Punjab demands that the ballot paper should be in Telugu, certainly it may be rejected. But a large number of people speak a particular language, not two languages. A controversy has been going on. It cannot be settled by not printing this or that. This has to be decided in such a way that no person is denied the privilege of voting. The hon. Minister will consider this.

Shri Hajarnavis: I will convey the views to the Election Commission.

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru): May I say that what you have been pleased to suggest is so

eminently reasonable that I do not see that it requires much consideration? It requires adoption.

National Universities

+

1:46. { **Shri Braj Raj Singh:**
Shri Harish Chandra
Mathur:
Shri Radha Mohan Singh:
Shrimati Maimoona Sultan:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to set up four national Universities in the country within the next ten years;

(b) whether out of these four national Universities one at New Delhi is being set up during the Third Five Year Plan;

(c) what are the details about the scheme as to money to be spent, sources of finances, course of study, number of students to be admitted, medium of instruction, site for University building and campus etc;

(d) whether in view of this proposal the scheme for a second University in Delhi has been shelved for the present;

(e) whether the scheme has been examined in all its details by the University Grants Commission; and

(f) the approximate time by which the work on the proposed national University in New Delhi will begin?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) No, Sir.

(b) to (f) Does not arise.

श्री बजरज सिंह: क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के समाचारपत्रों में प्रकाशित इस तरह के समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया था कि दिल्ली में अगले पांच साल के अन्दर तीसरी पांच वर्षीय योजना के अन्दर इस तरह के विश्वविद्यालय को स्थापित करने की योजना है ?